अमृत वाणी

अकेलापन कई बार अपने आप से सार्थक बातें करता है। वैसी सार्थकता भीड़ में या भीड़ के चिंतन में नहीं मिलती।
–राजेंद्र अवस्थी,

अब कहां गई पाकिस्तान की मित्रता

आज जब चीन में रहने वाले मुसलमानों का जीवन खतरे में है तो पाकिस्तान क्या कर रहा है और कहां है घड़ियाली आंसू बहाने वाले वे सारे अलगाववादी संगठनों के सरगना जिन्हें भारत में सम्मान पूर्वक सुकून भरा जीवन जीने वाले भारतीय मुसलमानों के जीवन में हमेशा कष्ट और दुख नजर आता है। चीन पाकिस्तान का सबसे घनिष्ट मित्र है और उसी देश में इस्लामधर्मी लोगों को परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है लेकिन न तो पाकिस्तान उसका विरोध करने की हिम्मत जुटा पा रहा है और न उसके अलगाववादी संगठन।

जैसा कि बताया गया है चीन अपने शिनजियांग प्रांत में मुसलमानों की पहचान खत्म करने की कोशिश में लगा है। वहां रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे है। यहां तक कि उन्हें उनके धार्मिक अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है।

मिली सूचना के अनुसार रमजान की शुरूवात होते ही मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में सरकारी अधिकारियों, छात्रों और बच्चों के रोजा रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध को कड़ाई से लागू भी किया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान अपने प्रमुख दोस्त के ऐसे व्यवहार पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। हास्यास्पद स्थिति यह है कि जहां सभी धर्मों के लोग भाईचारे और सदभाव के साथ शांति का जीवन व्यतित कर रहे हैं उस भारत देश में अनावश्यक एवं झूठी बाते फैलाते हुये लोगों को भड़काने एवं अशांति फैलाने से पाकिस्तान कभी बाज नहीं आता लेकिन जहां उसके स्वजातियों को वास्तव में उसके साथ और सहयोग की जरूरत है वहां आवाज उठाने की उसमें हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान के संरक्षण में पल बढ़ रहे अलगाववादी संगठनों की दशा भी एक जैसी ही है। कथित रूपसे इस्लाम और मुसलमानों के हितैषी होने का बड़े बड़े दावा करने वाले इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है।

इससे दो बातों का तो साफ संकेत मिलता है। एक यह कि ये अलगाववादी केवल अपने स्वार्थ के हितैषी होते है और किसी के हित से उनका कोई लेना देना नहीं है और दूसरी बात यह कि उनमें चीन की कार्रवाही के विरोध का साहस ही नहीं है।

यह सही समय है जब कश्मीर के उन कतिपय नवयुवकों को जो आज भी यह भ्रम पाल रहें है कि पाकिस्तान और वहां के अलगाववादी संगठन उनके हितैषी है इन हालातों को देखकर सबक लेना चाहिए। अन्यथा अगर वे अपने अंधे समर्थन के बल पर चलते रहेंगे तो एक दिन उनके सामने केवल अंधेरा ही रह जायेगा।

राज-काज

अतीक का मैदान छोड़ना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने वाले पूर्व सांसद अतीक अहमद के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनाव मैदान छोड़ने का एलान कर दिया है। वैसे तो अतीक इसका कारण पेरोल न मिलना बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ विरोधी भी हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की टीम के सामने घुटने टेक दिए हैं, इसलिए यूं मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वैसे राजनीतिक विश्लेषक तो यही कहते हैं कि अतीक अहमद ने समझदारी दिखाई है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते तो लालु जैसे जेल में होते और अब वो उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें भी नीतिश कुमार जैसा ही सम्मान प्राप्त हो जाएगा। दरअसल नीतिश कुमार भी अनेक मामलों में आरोपी हैं और यदि वो भाजपा के साथ नहीं जाते तो उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ सकती थी।

हवन और जनेऊ से क्या होगा

मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। इनके भाग्य का फैसला मतदाता कर चुका है जिसका खुलासा 23 मई को मतगणना के साथ हो जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गी राजा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा था कि श्ये कितने भी हवन करवा दें, ये कितने भी जनेऊ दिखला दें, पुलिस को भगवा ड्रेस भी सिलवा दें, लेकिन भगवा में जो आतंक के दाग लगाने की इन्होंने साजिश की है, उस पाप से ये बच नहीं पाएंगे। गौरतलब है कि यह चुनाव पूरी तरह धर्म और आतंकवाद पर आधारित हो गया था, क्योंकि जहां दिग्गी राजा को भाजपा अधर्मी बताने से गुरेज नहीं कर रही थी वहीं कांग्रेस साध्वी प्रज्ञा सिंह को मालेगांव मामले की आरोपी करार देते हुए भगवा आतंकवाद की याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में धार्मिक हवन और पूजा.पाठ भी खूब देखे गए, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या मोदी जी ने जो कहा वह सच हो पाता है या नहीं, क्योंकि मतदाता ने तो बहुत ही खामोशी के साथ अपना मत दान किया है।

परदे के पीछे से चल रही है चुनावी जंग

संपूर्ण...

सं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 1729252 है जबकि अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 392126 है। राज्य में 20 हजार से भी ज्यादा गांव है और करीब 90 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कुल 12 जिलों में विभाजित हिमाचल तीन डिवीजनों शिमला, कांगड़ा तथा मंडी में बंटा है। विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं जबकि लोकसभा की कुल चार सीटें हैं, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी तथा शिमला और इस प्रदेश में चुनावी मुकाबला सदैव भाजपा तथा कांग्रेस के बीच ही होता रहा है।

2014 के लोकसभा चुनाव में 53ण्85 फीसदी मत प्राप्त करते हुए चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज कराई थी जबकि 41ण्07 फीसदी मत प्राप्त करने के बावजूद कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। इस बार भी भाजपा की हरसंभव कोशिश है कि वह पिछली बार की जीत को पुनः दोहरा सके। हालांकि कांग्रेस ने भी चुनावी रण जीतने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी है। 2009 में कांग्रेस को एक तथा भाजपा को तीन सीटों पर जीत मिली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा कांग्रेस से सत्ता हथियाने में सफल रही थी। तब उसे 48.8 फीसदी मतों के साथ 44 सीटें मिली थी जबकि 41.7 फीसदी मतों के साथ कांग्रेस 21सीटों पर सिमट गई थी। एक सीट पर सीपीआई एम तथा दो सीटों पर निर्दलीय अपना परचम लहराने में सफल रहे थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 42.81 फीसदी मत प्राप्त कर 36 सीट हासिल कर सरकार बनाने में सफल हुई थी जबकि भाजपा को 38.47 फीसदी मतों के साथ 26सीटों पर संतोष करना पड़ा था।

इस बार कुल चार लोकसभा सीटों के लिए विभिन्न दलों के कुल 45 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतर रहे हैं। हालांकि यह तय है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस तथा भाजपा उम्मीदवारों के बीच ही रहेगा लेकिन राज्य के इतिहास में यह पहली बार देखा जा रहा है, जब प्रदेश की राजनीति का कोई भी सूरमा स्वयं चुनावी मैदान में नहीं उतरा है बल्कि तमाम बड़े.बड़े दिग्गज परदे के पीछे से ही अपनी.अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। शांता कुमार हों या वीरभद्र सिंह अथवा प्रेम कुमार धूमल या विद्या स्टोक्स, इनमें से खुद इस बार कोई भी चुनाव मैदान में नहीं है। वास्तव में हिमाचल में इस बार का लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों से ज्यादा उन नेताओं के बीच माना जा रहा है, जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन साख उन्हीं की दांव पर लगी है।

चारों लोकसभा क्षेत्रों का सिलसिलेवार विश्लेषण करें तो सबसे बड़ी हॉट सीट बनी है मंडी संसदीय सीट, जहां से रिकॉर्ड17 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनाव में कूद रहे हैं। इस हाई प्रोफ़ाइल सीट से पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुखराम के पोते आश्रय शर्मा चुनावी मैदान में हैं। अब तक आठ बार इस सीट पर सुखराम तथा वीरभद्र सिंह या उनके परिवार ने ही कब्जा किया है लेकिन पिछली बार भाजपा के रामस्वरूप शर्मा यह सीट झटकने में सफल रहे थे और भाजपा ने इस बार भी उन्हीं पर दांव लगाया है। हिमाचल की ष्छोटी काशीष् के नाम से विख्यात यह सीट सुखराम तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए निजी प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। 93 साल की उम्र में भी सुखराम खुद अपने पोते के लिए प्रचार करते और वोट मांगते घूम रहे हैं। एक ओर जहां मंडी संसदीय क्षेत्र को सुखराम का गढ़ माना जाता रहा है, वहीं जयराम ठाकुर सराज विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जो मंडी संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है, इसलिए वह भी अपना गढ़ बचाए रखने के लिए दिन.रात एक किए हुए हैं।

> **कुल चार लोकसभा सीटों वाले पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया के अंतिम चरण में 19 मई को मतदान होना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 55673 वर्ग किलोमीटर में फैले इस हिन्दू बहुल राज्य की कुल आबादी 6864602 है, जहां 95.17 फीसदी हिन्दू तथा 2.18 फीसदी मुस्लिम हैं। कुछ जिलों में तो हिन्दुओं की आबादी करीब 98 फीसदी तक है और मुस्लिम एक फीसदी से भी कम हैं। यही कारण है कि इस प्रदेश से न कभी कोई मुस्लिम विधायक रहा और न ही सांसद।**

कुछ साल पहले सुखराम के कांग्रेस से निष्कासन के बाद भले ही उनकी कांग्रेस में घर वापसी हो गई किन्तु हिमाचल सरकार में मंत्री रहे उनके बेटे अनिल शर्मा भाजपा में हैं जबकि सुखराम का पोता कांग्रेस का प्रत्याशी है। हालांकि अपने बेटे को लोकसभा टिकट मिलने के बाद अनिल शर्मा ने जयराम सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस सीट से प्रत्याशी भले ही रामस्वरूप तथा आश्रय हैं किन्तु वास्तव में परदे के पीछे असली मुकाबला पंण् सुखराम और जयराम ठाकुर के बीच ही है। मंडी के बारे में यह भी कहा जाता रहा है कि जो भी पार्टी यहां से चुनाव जीतती है, दिल्ली में उसी की सरकार बनती है। इसलिए भी यह सीट सर्वाधिक चर्चा का केन्द्र बनी हुई है। मंडी संसदीय क्षेत्र की कुल 17 विधानसभा सीटों में से फिलहाल 13 भाजपा के पास हैं और भाजपा इस सीट पर सुखराम तथा वीरभद्र सिंह के बीच बने छत्तीस के आंकड़े का फायदा उठाकर इतिहास कायम करना चाहती है।

हमीरपुर संसदीय सीट से कुल 11 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और भाजपा के अनुराग ठाकुर चौथी बार सांसद बनने के लिए मैदान में हैं। उनके मुकाबले कांग्रेस ने रामलाल ठाकुर को मैदान में उतारा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजेन्द्र सिंह राणा ने अनुराग ठाकुर को चुनौती दी थी किन्तु अनुराग से करीब एक लाख वोटों से हार गए थे। भाजपा को 35 फीसदी मतों के साथ यहां से कुल 448035मत मिले थे जबकि कांग्रेस को 28 फीसदी मतों के साथ 349632 वोट प्राप्त हुए थे। आप प्रत्याशी महज एक फीसदी मतों के साथ 15329 वोट पाने में ही सफल हुआ था।

दो बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके भाजपा के दिग्गज नेता शांता कुमार का गढ़ मानी जाने वाली कांगड़ा संसदीय सीट से 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने कैबिनेट मंत्री और गद्दी समुदाय के किशन कपूर पर दांव खेला है। पिछली बार इस सीट से शांता कुमार ही जीते थे किन्तु शांता कुमार द्वारा इस बार चुनाव लड़ने से इन्कार करने पर उनकी जगह किशन कपूर को मैदान में उतारा गया है, जिन्हें चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने जातीय समीकरण साधते हुए पिछड़ी जाति के पवन काजल पर दांव लगाया है। 2014 के चुनाव में विजयी रहे शांता कुमार को 456163 वोट मिले थे जबकि दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के चंदर कुमार को 286091 वोट मिले थे। यह सीट कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा की झोली में जाती रही है। 1951 में यह सीट कांग्रेस के हेमराज ने जीती थी और उसके बाद लगातार चार बार 1957, 1962, 1967 व 1971 में भी कांग्रेस ने ही यहां से जीत दर्ज की। 1977 में बीएलडी के दुर्गा चंद, 1980 में कांग्रेस के विक्रम चंद, 1984 में कांग्रेस की चंद्रेश कुमारी, 1989 में भाजपा के शांता कुमार, 1991 में भाजपा के डीडीखनोरिया, 1996 में कांग्रेस के सत महाजन, 1998 व 1999 में भाजपा के शांता कुमार, 2004 में कांग्रेस के चंदर कुमार और 2009 में भाजपा के डा. राजन इस सीट से विजयी रहे।

शिमला हिमाचल की एकमात्र आरक्षित सीट है, जहां से कुल छह प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां से 2009 से पहले भाजपा कभी भी जीतने में सफल नहीं हुई। उसके बाद वीरेन्द्र कश्यप लगातार दो बार चुनाव जीते। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा के वीरेन्द्र कश्यप 385973 वोट हासिल करके 84187 वोटों के भारी अंतर से जीते थे। उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के मोहनलाल को 301786 वोट मिले थे। इस बार भाजपा द्वारा उनकी जगह पच्छाद से बीजेपी विधायक सुरेश कश्यप पर विश्वास जताया गया है जबकि कांग्रेस ने सोलन से अपने विधायक कर्नलधनीरामशांडिल को कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान में उतारा है।

जहां तक चुनावी मुद्दों की बात है तो भाजपा जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम और काम के अलावा राष्ट्रवाद तथा सर्जिकलस्ट्राइक के मुद्दे पर चुनावी मैदान में मतदाताओं को रिझाने के लिए उतरी है, वहीं कांग्रेस विभिन्न मोर्चों पर केन्द्र सरकार की विफलता के साथ.साथ कांगड़ा तथा निचले हिमाचल से भेदभाव, हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा न दिए जाने तथा हिमाचल में विकास के मामले में भाजपा सरकार की नाकामी को भुनाने के लिए प्रयासरत है। विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा औद्योगिक विकास में कमी के आरोप, फलों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग, खराब सड़कें इत्यादि भी चुनाव के अहम मुद्दे बने हैं। बहरहाल, अब देखना यह है कि हिमाचल में परदे के पीछे से चल रही चुनावी जंग में भाजपा जीत का अपना पिछला रिकॉर्ड बरकरार रखने में सफल हो पाएगी या कांग्रेस उसकी सीटों में सेंध लगाने में सफल हो पाती है।

योगेश कुमार गोयल
(ये लेखक के अपने विचार है)

हेमंत करकरे का सच वही नहीं जो हमें बताया गया

हेमंत करकरे का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया है। भोपाल से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपनी उत्पीड़न की व्यथा बताते हुए कह गई कि हेमंत करकरे को मैने शाप दिया था। साध्वी की उम्मीदवारी के बाद से ही मौन धारण कर चुकी कांग्रेस बाहर आई और इसे शहीदों का अपमान बताया एवं भाजपा ने त्वरित प्रतिक्रिया दे दी कि हेमंत करकरे हमारे लिए शहीद हैं। साध्वी ने भी कह दिया कि इससे राष्ट्र विरोधियों को लाभ होगा मैं अपना बयान वापस लेती हूँ। किंतुए इससे अध्याय खत्म नहींए बल्कि दोबारा आरंभ हुआ है। सोशल मीडिया पर सघन बहस चल रही है। अंतर्धारा में यह इस चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। हेमंत करकरे की जान 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकवादी हमले में गई और साध्वी को मालेगांव द्वितीय धमाकों में हिन्दू आतंकवाद का खतरनाक चेहरा साबित करने का आधार उन्हीं के नेतृत्व में बना। इस तरह पूरे विवाद के दो पहलू हमारे सामने विचार के लिए हैं। क्या मुंबई आतंकवादी हमले में आतंकवाद निरोधक दस्ता या एटीएस प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका वाकई गौरवशाली थी दोए क्या मालेगांव विस्फोट के मामले में साध्वी प्रज्ञा सहित अन्य हिन्दुओं को संलिप्त साबित करने में उन्होंने निष्पक्ष पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। इतिहास भावनाओं के आधार पर नहींए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किसी की भूमिका का मूल्यांकन करता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर आतंकवादी हमले के समय वो वहां दिख रहे थे। इसका मतलब वे साहस के साथ मोर्चा पर आए। किन्तु जितने इत्मीनान से वे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहे थे उससे लग नहीं रहा था कि वे आतंकवादी हमले के विरूद्ध युद्ध के मोर्चे पर हैं। एटीएस सहित मुंबई पुलिस की आतंकवादी हमले के संदर्भ में आत्मघाती दयनीय समझए संघर्ष के लिए सामान्य व्यूह रचना का अभाव तथा आतंकवादियों के समक्ष बिल्कुल विफल हो जाने का आकलन उस जांच समिति ने किया जिसे तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने अत्यंत सीमित दायरे में जांच का जिम्मा दिया था। सरकार ने मांग के बावजूद अधिकार प्राप्त आयोग गठित नहीं किया। हालांकि अपनी सीमाओं में रहते हुए और भाषा मृदु रखते हुए भी आर डी प्रधान और वी बालाचन्द्रण समिति ने इनकी विफलताओं को उजागर किया। इसमें अनेक पुलिस अधिकारियों, सिपाहियों का नाम लेकर उनकी बहादूरी की प्रशंसा की गई है। किंतु मुंबई पुलिस आयुक्त तथा एटीएस प्रमुख करकरे की बिल्कुल प्रशंसा नहीं। क्विक रिस्पौंस टीम या क्यूआरटी तथा अस्सॉल्ट टीमें एटीएस की मुंबई शाखा के अंदर आती है। क्यूआरटी को जगह.जगह भेजा गया लेकिन समिति को उन्होंने कहा कि कोई अधिकारी नहीं था जो बताए कि करना क्या है। समिति ने लिखा है कि पूरा एटीएस अस्त-व्यस्त था। हेमंत करकरे प्रदेश एटीएस के प्रमुख थे। उनको योग्य एवं सक्षम तब माना जाता जब वे हमले के बाद क्विक रिस्पॉंस टीम को कमान के साथ दायित्वों का बंटवारा करते तथा स्वयं उनका मौनिटर करते। रिपोर्ट में अन्य पुलिस अधिकारियों के बारे में तो लिखा है लेकिन करकरे के पास हमले का सामना करने की योजना भी थी इसका जिक्र नहीं है। इसमें 7 अगस्त 2006 से 11 अगस्त 2008 तक के आठ खुफिया सुचनाओं की चर्चा है। ये सारे एकदम सुस्पष्ट और सटीक नहीं है किंतु इसमें लश्कर.ए.तैयबा द्वारा समुद्र मार्ग से आकर हमला करने की साजिशों की बात है। उदाहरण के लिए 9 अगस्त 2008 के खुफिया रिपोर्ट में दक्षिण मुंबई के ताज होटल, ओबेराय होटल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आदि पर हमले का अलर्ट है।

अवधेश कुमार
(ये लेखक के अपने विचार है)

राफेल पर सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ाई भाजपा की परेशानी

चुनाव आयोग के अब तक के इतिहास में ये पहला मौका है कि वो नरेन्द्र मोदी के सामने भाजपा के सामने बौना साबित हो रहा है। आयोग ने मुख्यमंत्री योगी के फैज पर दिये नारे ये तो मोदी की फैज है, इतने बड़े मामलों पर भी उन पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जिसके दो दिन बाद मोदी ने फिर से पाकिस्तान पर की गई हवाई कार्यवाही का ढोल पीट पीटकर फिर से उसका चुनावों में फायदा लेना चाहा जो चुनावी कानूनों के खिलाफ माना जा रहा है।

चुनाव आयोग तमाशबीन

उधर देश के नामचीन बड़े सेवानिवृत्त आला अफसरों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भी चुनाव आयोग के सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का मामला उड़ाया है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बजरंग बली व अलि के नामों पर फिर से जातपात भड़का कर वोटरों को प्रभावित करने पर जुटे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भाजपा को वोट देने और मोदी को पुन: प्रधानमंत्री बनाने के मामले में भी देखा गया है कि चुनाव आयोग सिर्फ पत्र भर लिख रहा है और तमाशबीन बनकर खड़ है।

फिल्मकारों का विरोध

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से भाजपा की पहले से ही नींद उड़ी है। उत्तर प्रदेश में चुनावों पर खोज खबर कर रहे बीण्बीण्सीण् लंदन के भारत में 30 साल तक रहे पत्रकार मार्कटली ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने मुजफ्फरनगर सीट पर देखा कि संघ परिवार ने यहां हिन्दू मुसलमानों को बांटने का अभियान भी अब प्रभावहीन सा लगने लगा है। 2013 में यहां दंगे कराकर ही बीजेपी 2014 में उत्तर प्रदेश में 73 लोकसभा सीट जीत पायी थी। अब ये माहौल नहीं है। जहां एक तरफ राफेल का मामला है वहीं सीबीआई और ईडी इन्कम टैक्स छापों से भाजपा विरोधी नेताओं को डराया जा रहा है। सीबीआई का दुरुपयोग तो 10.20 सालों से हो रहा है पर अब ये काफी निम्न स्तर पर किया जा रहा है। भाजपा उत्तर प्रदेश में 30.40 सीटेंए बिहार में 20.25 सीटें व मध्य प्रदेश में 20 के करीब सीटें व महाराष्ट्र में 25 सीटें व छत्तीसगढ़ में 10 सीटें खोने जा रही है की खबरें आ रही हैं। जो करीब 100.120 के लगभग हो जाती हैं। इसकी भरपाई आखिर बंगाल या उड़ीसा से कितनी होगी। सियासी पंडित यहां से सिर्फ 8.10 सीटें ही मान कर चलते हैं। उधर फिल्मकारों ने भी आम जनता से मोदी को वोट न देने की अपील की है। उनका मानना है कि गाय के नाम पर दलित और मुसलमानों पर संघ परिवार हिंसा फैला रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की दखल पर राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सरकारों को कुछ कार्यवाही हत्यारों पर करनी पड़ी थी। संघ परिवार के मुखिया तक ने गोवंश के मामले में हत्यारों की वकालत तक की थी उत्तर प्रदेश। में चीनी मिलों के बकाया 60 हजार करोड़ को किसालों को दिलाने में भी उत्तर प्रदेश सरकार 2 साल की कोशिशों पर भी नाकाम रही है। किसानों को महज 14 हजार करोड़ रुपये बमुश्किल दिलाये जा सके हैं। भाजपा को इन चुनावों में काफी निराशा भी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में तो उसे 10 सीटों पर प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहे हैं। उधर भोपाल में दिग्विजय सिंह के खिलाफ15 दिन में भी कोई प्रत्याशी नहीं उतार पायी है। भाजपा के एक केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को ग्वालियर से मोदी लहर में भी मुश्किल से 26 हजार वोटों से जीत पाये थे। ऊपर से उन्होंने ग्वालियर चम्बल संभाग में नरेन्द्र तोमर ने अपने ही भाजपा वालों को प्रशासन की मदद से पीछे धकेल कर चुनावों में भी परेशान करवा कर हरवा दिया था। अपने पुत्र मोह में भी नरेन्द्र काफी बदनाम रहे हैं। उनके बेटे ने उनके ही बंगले में समान्तर सरकार चलाते हुये देखे गये।

मुश्किल से तोमर जीते थे

मध्य प्रदेश में भी नरेन्द्र तोमर को इस बार चुनकर दिल्ली जाने में लाले पड़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो इस बार ग्वालियर से मुरैना चले गये हैं। वहां भी विरोध हो जाने से वो घबराकर अब खुद कहने लगे हैं कि मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कहां से लड़ने वाला हूँ। उधर शिवराज सिंह ने अपने बयान में कहा है कि ग्वालियर चम्बल में करारी हार से मैं पुनरू मुख्यमंत्री नहीं बन पाया हूँ। उधर नरेन्द्र तोमर के बंगले पर जहां हजारों की भीड़ रहती थी अब वहां सैकड़ों भी कार्यकर्त्ता नहीं बचे हैं। उधर राफेल पर सरकारी झूठ के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने पुनरू मामले में सुनवाई स्वीकार कर भाजपा इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के नाम के दुरुपयोग के गुब्बारे को सरेआम फोड़ दिया है व सरकारी दस्तावेजों के सामने प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। लगता है राफेल के मामले में भाजपा व नरेन्द्र मोदी की मुश्किलें फिर से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उधर बेरोजगारी के मुद्दे पर भी नरेन्द्र मोदी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चौकीदार चौक का नारा अपनी लोकप्रियता पर परवान चढ़ता दिख रहा है।

नईम कुरैशी
(ये लेखक के अपने विचार है)